

विवेकपूर्ण मतदान की घुनौती

अंजय बोकिल

भाजपा और कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों के 18 वीं लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। कुछ के होने वाले हैं और बाकी कुछ के लिए घोषणा पत्र जारी करने से ज्यादा चिंता अपना राजनीतिक वज्रबद्ध बचाने की है। सरसवी तौर पर भेदखाना जाए तो सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र में रेवड़ी कल्चर का अधिकाधिक विस्तार और हो गई है। बल्कि यूं कह कि अपने वैचारिक फैम में रेवड़ी संस्कृति को फिट करने और उसके औचित्य को जताने की पुरुजोर कोशिश है। अब तक के अनुभव को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस पार्टी का घोषणा पत्र जितना लोक लुभावन और 'रेवड़ी पैक' होता है, उसके सत्ता में आने की संभावना उतनी ही कम होती है।

इसका सीधी अर्थ यह है कि जिस पार्टी का राजनीतिक जनाधार जितना कम होता है, उसकी सियासी शिक्षकेबाजी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर आप इसी पैमाने पर सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की टैरिंग करें तो सचाई समझ आ जाएगी। इसी के साथ यह सबाह भी नर्ती है कि चुनावों में मतदाता या देखने वाले के बाद अब स्वैरिंग के लिए प्रोत्साहन है, वहाँ महिलाओं के लिए तीन करोड़ और लखपति दीदी, ड्रोन पायलट का वादा भी मायने रखता। गरीबों के लिए अगले पांच साल तक मुफ्त खाद्यान का वादा भले पुराना है लेकिन 80 करोड़ से अधिक परिवर्तों के लिए आगले पांच साल तक मुफ्त राशन की योजना की गारंटी मायने रखती है। गरीबों को पीपम आवास में और तेजी लाने का वादा भी अमर है। कोरोना की आपादा में मुफ्त वैक्सीन के बाद अब स्वैरिंग के केंसर से मुक्त महिला भी जायी रहती है एवं मरमत लानाने वाली सवित्र हो सकती है। किसानों पर करम, बिजली बिल शून्य, रेहड़ी-टटरी बालों और गांवों तक चिन्हियां प्रदान करने के लिए विकास संदेश भी सियासी जमीन पर बोटों की फसल लालहाने में कारगर सवित्र हो सकती है। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ इलाज 20 लाख करना युवाओं और हुनरमंदों के लिए प्रोत्साहन है, वहाँ महिलाओं के लिए तीन करोड़ और लखपति दीदी, ड्रोन पायलट का वादा भी मायने रखता।

देश के चुनाव नर्तीजों के ट्रैड को समझते हों तो बीच वर्षों से मतदाता वैचारिक अग्रह-दुराग्रही और शाब्दिक लफाजों के जांसों में ए और बगर मतदान के लिए उन बातों को प्रार्थित करते हैं। लेकिन तृष्णा से आबद्ध प्राणि-समूह किसी के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते कि वे किसी को किरण (लाइट) हैं। कैमरा है विकास और विरासत पर प्रहर के। जनादेश 2024 का टीजर जारी हो रहा चुका है। संवाद, लाइट, कैमरा, एक्शन के बाद अब यह देखना दिलचस्प बन गया है कि 4 जून को जब लोकतंत्र का जनादेश (चुनाव नर्तीजे) रिलीज होता है तो बॉक्स ऑफिर पर चार सौ सीटें (4 सौ करोड़ का बिजनेस) पायी हैं या नहीं। बकौल मोदी- यह तो ट्रेलर है..... पिक्कर अभी बाकी है। ऐसे में आपकी तरह हमें भी है 4 जून का इंतजार।



आधारित है। इस घोषणा पत्र की भावना अच्छी है, लेकिन वारे हावाई ज्यादा है। कौप्रिस के घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा सबकी महालझी योजना का है। इसके तहत गरीब परिवर्तों की सीधी एक लाख रुपये नकद देना का वादा है। देश में विवेकपूर्ण परिवर्तों की झलक मिलती है। इसे जानकर मतदाता यह तय कर सके कि किसे बोट देना बेहतर होगा, कौन देश अथवा प्रदेश को ठीक से चला सकता है, किसमें एक आम नागरिक की मूलभूत समयाओं का निदान कर उसकी जिंदगी सुलभ बनाने की क्षमता और इच्छाशक्ति है। लेकिन मतदाता हमेशा इसी आधार पर बोट दें, वह जरूरी नहीं है।

वह प्रसंगनुरूप प्राथमिकताएं तय करके भी कई बार बोट करता है। इसीलिए एक बार जारी घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियों को भी अगले चुनाव में याद नहीं रहता। वो जनभावनाओं और अपेक्षाओं को रेटिंगों के माध्यम से राजनीतिक दोहन का अधिकाधिक प्रयास करते दिखते हैं। क्योंकि घोषणा पत्रों के फिर मतदाता का होरेक का अपना एक इको सिस्टम होता है, जिसके अनुरूप बोट वॉट डालता है? बोटर के सामने बड़ी चुनौती यही है कि वह विवेकपूर्ण ढंग से मतदान कैसे करें?

देश के चुनाव नर्तीजों के ट्रैड को समझते हों तो बीच वर्षों से मतदाता वैचारिक अग्रह-दुराग्रही और शाब्दिक लफाजों के जांसों में ए और बगर मतदान के लिए उन बातों को प्रार्थित करते हैं। लेकिन न किसी न रूप में सीधा फायदा पहुंचती हैं फिर वह चाहे नकदी के रूप में हों, अवसर के रूप में हो या सुरक्षा अथवा आश्वस्ति के रूप में हो। वह जान चुका है कि चुनाव घोषणा पत्र है चुनावी साबित में नए सिरे से किया जाने वाला राजनीतिक विस्तार के लिए 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ-साथ तमिल भाषा के साथ-साथ बुलेट ट्रेन की रफरत के माध्यम से पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण सभी को पीपम आवास में और तेजी लाने का वादा भी अमर है।

भाजपा के बाबत की अपादा में मुफ्त वैक्सीन के बाद अब स्वैरिंग के केंसर से मुक्त महिला भी जायी रहती है एवं आगले पांच साल तक मुफ्त खाद्यान का वादा भले पुराना है लेकिन 80 करोड़ से अधिक परिवर्तों के लिए आगले पांच साल में रेवड़ी योजना की क्षमता और जमीन नहीं रहती है। गरीबों के लिए निवेश से नौकरी तक का वादा कर मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख से बढ़ाव करना युवाओं और हुनरमंदों के लिए प्रोत्साहन है, वहाँ महिलाओं के लिए तीन करोड़ और लखपति दीदी, ड्रोन पायलट का वादा भी मायने रखता।

यहाँ अपने विवेकपूर्ण ढंग से मतदान कैसे करें? देश के चुनाव नर्तीजों के ट्रैड को समझते हों तो बीच वर्षों से बदल जाने के बाद नियमित रूप से बाहर निकले थे। वहाँ अब मोदी सरकार का दावा है कि वही बोट देस से बाहर निकले थे। वहाँ अब जमीन नहीं रहती है। उधर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रतिवर्ष एक बार जारी किया है। विकास की दिशा वही रहे, जो उसने तय कर रखी है। उधर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रतिवर्ष एक बार जारी किया है। विकास की दिशा वही रही है।

माकपा ने भारत के परमाणु नियन्त्रीकरण का वादा भी किया है। विश्व शांति के आग्रह से उपजे इस वादे में देश को सम्बन्धित करने के लिए 3 खरब रुपए चाहिए। ये कहाँ से आएंगे, स्पष्ट नहीं है। वैसे देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम का दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की आधिक नीतियों की वजह से देश में 10 सालों में 24 करोड़ लोग गरीबी परेखा से बाहर निकले थे। वहाँ अब मोदी सरकार का दावा है कि वही बोट देस साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले (नीति आयोग को प्रिपोर्ट)। अगर दोनों को सही मान लिया जाए तो बोट 20 साल में कुल 50 हजार करोड़ आवादी जो कि कुल आवादी का एक तिहाई है, गरीबी रेखा से बाहर आ चुकी है। तो पिर सरकार किंवदंशी 80 करोड़ बीपीएल परिवर्तों को मुफ्त राशन दे रही है?

कांग्रेस जित जनगणना का वादा भी कर रही है, जिसकी जब चुनौती से खुद घोषणा के अग्रही ने 1962 वाले दोरे में लै जाने का वादा भी कर रहा है। मजेदार बात है कि इंडिया गतवर्धन के सत्ता में आपने त्यार दिवार में 200 यूनिट फ्लॉट बिल्डली दी जाएंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 1 लाख 60 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा।

माकपा ने भारत के परमाणु नियन्त्रीकरण का वादा भी किया है। विश्व शांति के आग्रह से उपजे इस वादे में देश को सम्बन्धित करने के लिए 3 खरब रुपए चाहिए। ये साथ में लौटे पर आम देशी ज्यादा ज्यादा ज्यादा ज्यादा है।

एक समय था जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हुआ करते थे। वामपाथी इतिहासकार मुद्रुला मुखर्जी ने एक बार जारी घोषणा पत्र में लौटे आपले दोरे में लै जाने का वादा भी कर रहा है। मजेदार बात है कि इंडिया गतवर्धन में आपने त्यार दिवार में 200 यूनिट फ्लॉट बिल्डली दी जाएंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 1 लाख 60 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा।

एक समय था जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हुआ करते थे। वामपाथी इतिहासकार मुद्रुला मुखर्जी ने एक बार जारी घोषणा पत्र में लौटे आपले दोरे में लै जाने का वादा भी कर रहा है। मजेदार बात है कि इंडिया गतवर्धन में आपने त्यार दिवार में 200 यूनिट फ्लॉट बिल्डली दी जाएंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 1 लाख 60 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा।

उधर भाजपा के 'संकल्प पत्र' में किसी नहीं है। लोकांतरुभाव योजना का वादा नहीं है, नैतिकों में भारी खबरबद्ध है। कृषि उत्पादन के लिए 3 खरब रुपए देस से बाहर निकले। अगर दोनों को सही प्रतिवर्ष एक बार जारी किया जाए तो बोट 3 खरब रुपए देस से बाहर निकले। इसके बाद जारी घोषणा पत्र में जनगणना का वादा नहीं है, नैतिकों में भारी खबरबद्ध है।

उधर भाजपा के 'संकल्प पत्र' में किसी नहीं है। लोकांतरुभाव योजना का वादा नहीं है, सिवाय आयुष्मान योजना में बुजुंगों को सम्मिलित करने के। पार्टी आत्म संकल्प और अप्रमुखता के द्वारा भी ज्यादा ज्यादा जारी है। यहाँ अपने विवेकपूर्ण ढंग से बाहर निकले। यहाँ अपने विवेकप

बस्तर में मोडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एयर एंबुलेंस की तैनाती, अब तक 110 करोड़ जल्द

पहले चरण का मतदान 19 को, आज से रवाना होगी टीमें



रायपुर। बस्तर में 19 अप्रैल कार्य में लगे कर्मचारियों और को पहले चरण का चुनाव होना है। इसके लिए निवाचन आयोग की टीम ने पुख्ता बंदेबस्त कर चरण के मतदान के लिए अलग-अलग शहरों में चेकिंग के दौरान अब तक करीब 110 करोड़ रुपए जल्द किए हैं। जिसमें 1 जनवरी 2024 से 16 मार्च तक 66.03 करोड़ और 16 मार्च से 14 अप्रैल तक 43 करोड़ 97 लाख रुपए शामिल हैं।

आज सोमवार को तृतीय चरण अंतर्गत नामांकन के कार्यालयों के 15 अध्यर्थियों के 32 नामांकन दखिल हुए हैं। इसमें सरगुजा 4, सरगढ़ 2, जंगीर 3, बिलासपुर 4, दुर्ग 9 और रायपुर से 10 इस

तिथि 22 अप्रैल है।

चुनाव के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर चुनाव आयोग की चैनी नजर है।

निवाचन आयोग की टीम ने अलग-अलग शहरों में चेकिंग के दौरान अब तक करीब 110 करोड़ रुपए जल्द किए हैं। जिसमें 1 जनवरी 2024 से 16 मार्च तक 66.03 करोड़ 2 और 16 मार्च से 14 अप्रैल तक 43 करोड़ 97 लाख रुपए शामिल हैं।

आज सोमवार को तृतीय चरण अंतर्गत नामांकन के कार्यालयों के 15 अध्यर्थियों के 32 नामांकन दखिल हुए हैं। इसमें सरगुजा 4, सरगढ़ 2, जंगीर 3, बिलासपुर

की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। नामांकन भरने पदाधिकारी शैलाभ साहू ने दी है।

शैलाभ साहू ने बताया कि,

नामांकन पत्रों की संक्षिका 20

अप्रैल एवं रायपुर से 10 इस

तरह 15 अध्यर्थियों से कुल 32

नामांकन दखिल हुए हैं।

लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रथम चरण में 159 मतदान केंद्र तथा द्वितीय चरण के कुल 112 मतदान केंद्र सर्वदेशीय के रूप में चिन्हित किए गए हैं। प्रथम चरण के लिए 69 रत्न तथा द्वितीय चरण के लिए 132 स्नर की व्यवस्था की गई है। सेक्टर अफिसर एवं ईवीएम-वीवीपैट के परिवहन के लिए कुल 11644 वाहनों में जीपीएस स्थापना किया जाना है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से 274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत प्रथम चरण

के 6 जिलों के 1021 वाहनों में से

274 वाहनों में जीपीएस डिवाइस

स्थापित की जा चुकी है।